

5. निर्वाचन (Elections)

5.1. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक {Election Laws (Amendment) Bill}

सुझियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया।

इस विधेयक के बारे में

- इस विधेयक में कुछ चुनावी

सुधारों को लागू करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950¹⁰ और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951¹¹ में संशोधन करने का प्रावधान है।

संशोधन द्वारा लाये गए बदलाव इस प्रकार हैं (तालिका में देखें):

संशोधन	मूल प्रावधान	किये गए परिवर्तन
मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ना (RPA, 1950 की धारा 23 में संशोधन द्वारा)	<ul style="list-style-type: none"> • 1950 के अधिनियम में प्रावधान है कि एक व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। • सत्यापन के पश्चात् यदि अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक पंजीकरण का हकदार है तो वह आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश देगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कह सकता है कि अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए। • यदि उस व्यक्ति का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो इसमें दर्ज विवरणों के सत्यापन¹² के लिए आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। • यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। <ul style="list-style-type: none"> ○ ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।
मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि (RPA, 1950 की धारा 14 के खंड (b) में संशोधन द्वारा)	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 1950 के अधिनियम के तहत जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जाती है, उस वर्ष की 1 जनवरी को नामांकन की पात्रता तिथि माना जाता था। • इसका तात्पर्य यह है कि 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष का (अर्थात् मतदान के लिए पात्र) होने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में तभी नामांकन करा सकता था, जब अगले वर्ष के लिए मतदाता सूची तैयार/संशोधित की जाए। 	<ul style="list-style-type: none"> • यह विधेयक एक कैलेंडर वर्ष में चार पात्रता तिथियाँ प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है, जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी।
लिंग-तटस्थ या जेंडर-	<ul style="list-style-type: none"> • 1950 का अधिनियम कुछ ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचक 	<ul style="list-style-type: none"> • विधेयक के द्वारा RPA, 1950 और 1951 में 'पत्नी

¹⁰ Representation of the People Act (RPA), 1950

¹¹ Representation of the People Act, 1951

¹² Authentication of Entries in the Roll